अध्याय IV: संघ क्षेत्र
(वाणिज्यिक क्षेत्र)

लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड

4.1 मिनिकॉय में टूना कैनिंग फैक्टरी का आधुनिकीकरण

1500 कैन प्रति दिन से 10,000 कैन प्रति दिन तक टूना कैनिंग फैक्टरी, मिनिकॉय की क्षमता के उन्नयन का कच्चे माल (टूना) की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना अनुमोदन किया गया था। यूटीएल प्रशासन यह भी सुनिश्चित करने में विफल रहा कि एलडीसीएल से भिजवाए प्रस्तावों को इसके निदेशक बोर्ड की स्वीकृति थी तथा तद्नुसार उनकी सवीक्षा की गई थी। आगे, वित्त नियमावली का अनुपालन करने में कृषि एवं मत्स्य पालन मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप ₹7.64 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा छः वर्षों से अधिक के लिए ₹6.89 करोड़ अवरूद्ध पड़े रहे।

4.1.1 प्रस्तावना

लक्ष्द्पीप विकास निगम लिमिटेड (एलडीसीएल) 1990 से मिनिकॉय, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में टूना कैनिंग फैक्टरी को चला रहा है। मस्त्य पालन विभाग यूटीएल के पास एलडीसीएल के 99.99 प्रतिशत शेयर हैं तथा शेष कार्यालय सग्रांहक सह विकास आयुक्त, यूटीएल के स्वामित्व के हैं। कार्य स्थिति तथा अप्रचलन के कारण तीन लाख कैन प्रति वर्ष की संस्थापित क्षमता वाली फैक्टरी का उत्पादन वर्षों तक इसकी क्षमता से कम[1] हुआ है।

एनआईएफपीएफएटीटी[2] द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर एलडीसीएल ने फैक्टरी का सुधार तथा इसे आधुनिकीकृत करने तथा 1500 से 10,000 कैन प्रति दिन (अर्थात् तीन लाख कैन से 20 लाख कैन प्रति वर्ष) तक उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव किया था (नवम्बर 2009)।

---

[1] 61,550 कैन (2013-14), 42,586 कैन (2014-15) तथा 88,128 कैन (2015-16)।

[2] नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एण्ड ट्रेनिंग, एक भारत सरकार की संस्था।

कृषि एवं मत्स्य पालन मत्रांलय से प्राप्त निधियों में से यूटीएल प्रशासन ने जनवरी/फरवरी 2010 में एलडीसीएल को ₹4.40 करोड़ जारी किए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भी ₹7.64 करोड़ की कुल परियोजना लागत के प्रति एएसआईडीई[3] के तहत ₹3.24 करोड़ स्वीकृत किए (जून 2010)। बाद में एलडीसीएल ने परियोजना के कार्य क्षेत्र को अर्ध स्वचालित फैक्टरी से पूर्णतः स्वचालित फैक्टरी में संशोधित किया (जुलाई 2010) तथा यूटीएल प्रशासन ने कृषि एवं मत्स्य पालन मंत्रालय की अनुदान में से ₹13.78 करोड़ (परियोजना लागत: ₹12.75 करोड़; कार्यशील पूंजी: ₹1.03 करोड़) की लागत हेतु अतिरिक्त निधिया[4] जारी की।

एलडीसीएल ने मत्स्य पालन विभाग को ₹32.15 करोड़ के संशोधित अनुमान (सितम्बर 2013) प्रस्तुत किए। इन अनुमानों में अकेले सिविल निर्माण कार्य घटक को ₹4.40 करोड़ से ₹9.73 करोड़ तक बढ़ाया गया था। मत्स्य पालन विभाग ने संशोधित अनुमानों पर निर्णय नहीं लिया है जो प्रशासक की प्रत्यायोजित शक्तियों के ₹20 करोड़ से अधिक है।

लेखापरीक्षा में पाए गए महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

4.1.2 अर्द्ध-स्वचालित कैनिंग प्रक्रिया की अवास्तविक लागत

एनआईएफपीएचएटीटी. अनुमानों (2009) के आधार पर, एलडीसीएल. बोर्ड ने अनुमोदित किया और यूटीएल प्रशासन ने ₹7.64 करोड़ की परियोजना लागत को पूरा करने के लिए निधियां जारी की थी, जिसमें से सिविल निर्माण कार्यों का अनुमान ₹4.40 करोड़ तक लगाया गया था। यह सिविल निर्माण कार्यों के लिए एलपीडब्ल्यूडी. द्वारा अनुमानित ₹8.50 करोड़ से कम था। परिणामस्वरुप बोर्ड के आग्रह पर एलपीडब्ल्यूडी के समक्ष संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए थे जोकि ₹3.51 करोड़ (23 सितम्बर 2010) के लिए अनुमोदित किए गए थे। आधुनिकीकरण ठप्प होने के पश्चात् जीटीसीएस कोची जिसे एलडीसीएल द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने आधुनिकीकरण की स्थिति

[3] सेन्ट्रल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर डेवलपिंग एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड अदर एलाईड एक्टिविटिज (एएसआईडीई) स्कीम।

[4] कुल निर्गम - कृषि एवं मत्स्य पालन मंत्रालय ₹8.45 करोड़ (राजस्व शीर्ष) ₹2.00 करोड़ (पूंजीगत शीर्ष), वाणिज्य मंत्रालय ₹3.24 करोड़ (पूंजीगत शीर्ष)।

पर एक डीपीआर प्रस्तुत किया था (सितम्बर 2013)। डीपीआर को अग्रेषित करते हुए, एलडीसीएल ने यूटीएल प्रशासन को सूचित किया कि अर्द्ध-स्वचालित कैनिंग प्रक्रिया पर एनआईएफपीएचएटीटी के अनुमान त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि ₹7.64 करोड़ की लागत में (i) सिविल निर्माण कार्यों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की बाजार निविदाएं या दरों की विभागीय अनुसूची (डीएसआर) और (ii) नए भवन, प्रशीतन और शीतगृह के अनुमान एचएसीसीपी[5]/यूरोपीयन यूनियन मानकों सहित टूना कैनिंग कारखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ मेल नहीं खाना; शामिल नहीं था। इसके अतिरिक्त, एनआईएफपीएचएटीटी द्वारा उद्देशित रूप से मौजूदा कारखाने को न गिराने का यूटीएल प्रशासन का फैसला (12 जुलाई 2010) और उसकी बजाय निकटवर्ती भूमि पर नई संरचना का निर्माण करने (और उसके पश्चात् पुरानी ईमारत को गिराने) के निर्णय ने डिजाईन को काफी जटिल बना दिया था।

यह तथ्य कि मौजूदा ईमारत को रखने और एक अलग नई ईमारत का निर्माण करने के निर्णय के पश्चात् लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग (एलपीडब्ल्यूडी) जोकि कार्यान्वयन अभिकरण था, उसके द्वारा सिविल निर्माण कार्यों पर एनआईएफपीएचएटीटी के अनुमानों पर पुनरीक्षण न किया जाना, एनआईएफपीएचएटीटी के डीपीआर में आवृत्त आवश्यक मदों को हटाकर अनुमानों की बाद में कमी और अनुमानों का संशोधन न किया जाना यह दर्शाता है कि अर्द्ध-स्वचालित प्रक्रिया के लिए सिविल निर्माण-कार्यों की लागत अवास्तविक थी।

4.1.3 पूर्ण स्वचालित प्रक्रिया में बदलने का विवेकहीन निर्णय

4.1.3.1 10,000 कैन प्रति दिन तक क्षमता बढ़ाने का विवेकहीन निर्णय

एलडीसीएल का प्रतिदिन 1,500 से 10,000 डिब्बे की क्षमता प्रतिदिन बढ़ाने का निर्णय बिना किसी आधार का था। एनआईएफपीएचएटीटी का डीपीआर, अनुमोदित किया गया था जिसके आधार पर परियोजना आधारित थी, में अस्वीकरण निहित था कि इसने कच्चे माल (टूना) की उपलब्धता का आकलन

[5] जोखिम विश्लेषण और गंभीर नियंत्रण बिंदुए यह अंर्तराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य प्रबंधन प्रणाली है जो उत्पादन प्रक्रियाओं में जैविक, रसायनिक और भौतिक जोखिमों जिनके कारण अंतिम उत्पाद असुरक्षित हो जाता है, उनसे खाद्य सुरक्षा के लिए एक व्यवस्थित निवारक दृष्टिकोण का समर्थन करता है और सुरक्षित स्तर तक इन जोखिमों को घटाने के लिए माप डिजाइन करते है।

करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था और रिपोर्ट इस कल्पना के साथ तैयार की गई थी टूना की पर्याप्त मात्रा मौजूद थी।

योजना आयोग ने अनुमान[6] लगाया था कि लक्षद्वीप के आसपास संभव उपयोग क्षमता लगभग 50,000 टन थी जबकि वास्तविक क्षमता केवल 10,000 टन थी। उत्पादन केवल मदर वैसल को लगाने से होगी जोकि छोटे मछली पकड़ने वाले जहाजों की बड़ी संख्या को बहुत दूर के मछली पकड़ने वाली जगहों पर ले जा सकते हैं। वर्तमान समय में, लगभग 1,200 टन अतिरिक्त कैच (स्थानीय उपभोग के बाद) को 'मासमीन' (परंपरागत स्मोक्ड टूना) में परिवर्तित कर दिया जाता है और महाद्वीप पर बेच दिया जाता है। एलडीसीएल दिसम्बर 2009 से अगात्ती में मासमीन पैकिंग यूनिट का परिचालन कर रहा है और सभी द्वीपों से एकत्रित मासमीन का निर्यात भी करता है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) विशेषज्ञ दल ने भी सूचित किया (मार्च 2016) कि तीन चौथाई स्थानीय टूना कैच को मासमीन के लिए भेज दिया जाता है और शेष में से केवल कुछ अंश मौजूदा कैनिंग कारखाने को जाता है जोकि प्रतिदिन 1,000 डिब्बों की क्षमता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इसके अलावा, कच्चे माल की अनुपलब्धता और नांव की मरम्मत के कारण कारखाने में एक वर्ष में केवल 9 महीने कार्य होता है।

एनआईएफपीएचएटीटी का डीपीआर भी निर्धारित करता है कि आर्थिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए अर्द्ध-स्वचालित संयंत्र को वर्ष में कम से कम 10 महीनों के लिए कार्य करना होगा। इस प्रकार, आर्थिक व्यवहार्यता को प्राप्ति हेतु 10,000 डिब्बों की क्षमता वाले अर्द्ध-स्वचालित कारखाने में 880 एमटी टूना[7] की आवश्यकता होगी जोकि केवल तब ही प्राप्त किया जा सकता है जब स्थानीय मछुआरे और एलडीसीएल कैनिंग कारखाने को अपने मौजूदा मासमीन उत्पादन के लगभग तीन चौथाई भाग को विपथित करते है जिसकी संभावना कम है।

---

[6] लक्षद्वीप विकास रिपोर्ट, 2007

[7] 10,000 डिब्बे x 220 दिन अर्थात् 22 लाख डिब्बे। एक किलो कच्चे टूना को टूना के 2.5 डिब्बों से अधिक प्रदान करना चाहिए।

एमपीईडीए विशेषज्ञ दल ने सूचित किया कि आधुनिकीकरण परियोजना को मछली पालन विभाग के इस आश्वासन पर लिया गया था कि वह दो मदर वैसलों का प्रापण करेंगे और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास करेंगे। लेखापरीक्षा को दिए गए एलडीसीएल के उत्तर द्वारा इसका समर्थन किया गया था (9 जून 2015) कि निदेशक मंडल को सूचित किया गया था कि मछली पालन विभाग द्वारा मदर वैसल द्वारा कच्चे माल (टूना) की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा, यह अपेक्षा नहीं की गई थी उच्च लागत के कारण मदर वैसल के प्रापण हेतु प्रस्ताव से इंकार कर दिया जाएगा (नवम्बर 2012)। हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया बोर्ड के आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यवृत्त में मदर वैसल के प्रापण पर चर्चा नहीं की गई है। एलडीसीएल ने बाद में लेखापरीक्षा को सूचित किया (18 मई 2016) कि आधुनिकीकरण के संबंध में मदर वैसल के प्रापण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं था और पहले के प्रस्ताव को हटा दिया गया था क्योंकि वह बहुत महंगा था। एलडीसीएल ने यह भी स्वीकार किया (14 अक्तूबर 2016) कि डिब्बे वाले टूना के लिए राष्ट्रीय और अंर्तराष्ट्रीय बाजारों पर काई बाजार सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि गहरे-समुद्र की मछली सुविधाओं के बिना पर्याप्त कच्चे माल की अनुपस्थिति और 10,000 डिब्बे वाले टूना के लिए देशीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर सूचना की कमी में डिब्बे प्रतिदिन की क्षमता को बढ़ाने की परियोजना विवेकहीन थीं।

4.1.3.2 पूर्ण स्वचालित प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त कच्चा माल (टूना)

अपर्याप्त कच्चे माल पर लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति के उत्तर में, एलडीसीएल ने स्वीकार किया (अगस्त 2016) कि प्रापण किए गए पूर्ण-स्वचालित उपकरण का न्यूनतम क्षमता उत्पादन (अर्थात् जिसके नीचे मशीनरी कार्य नहीं करेगी) 1,145 कैन प्रति घंटा थी। इसमें पूर्ण क्षमता उपयोगिता हेतु 806.08 एमटी टूना की आवश्यकता है। यदि लक्षद्वीप के सभी द्वीपों (132 एमटीप्रति वर्ष) में टूना मछली की संपूर्ण उतारी गई क्षमता (सामान्य राष्ट्रीय सेवन और मासमीन उत्पादन सहित) को मछली कैनिंग कारखाने में विपथित किया जाए तब भी पूर्ण स्वचालित कैनिंग कारखाना वर्ष में केवल 60 दिनों के लिए कार्य कर पाएगा। वास्तव में, मौजूदा कारखाने में भी उत्पादन मुख्य रूप से कच्चे माल

की कमी के कारण से कम है, तो इसका अर्थ होगा कि मौजूदा कैनिंग कारखाने के भी 17 नियमित और 14 आकस्मिक कर्मचारी वर्ष में अधिकतर समय के लिए बिना कार्य के रहेगे जिससे कि कैनिंग कारखाने का प्राथमिक उद्देश्य जोकि स्थानीय मछुआरे की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है, पूरा नहीं हुआ।

4.1.3.3 बदलने के निर्णय में उचित प्रक्रिया को अनदेखा करना

(i) गृह मंत्रालय ने प्रशासक की प्रत्यायोजित शक्तियों को ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़ तक कर दिया था **(**5 जुलाई 2010**)**। इन आदेशों की प्राप्ति की तिथि (12 जुलाई 2010) पर, प्रशासक ने स्वयं की अध्यक्षता में एलडीसीएल अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता के रुप में कारखाने को अर्द्ध-स्वचालित से पूर्ण स्वाचालित के रूप में बदलने का निर्णय लिया। इस स्तर पर मंडल को अनदेखा करके एलडीसीएल ने अतिरिक्त निधियों के लिए यूटीएल प्रशासन के समक्ष प्रस्ताव रखा। चूंकि प्रस्ताव में एलडीसीएल अध्यक्ष की क्षमता में प्रशासक का अनुमोदन था, यूटीएल प्रशासन ने भी प्रस्ताव के गुणों की जांच किए बिना निधियां जारी की थीं। यद्यपि, 85वीं (17 दिसम्बर 2010), 86वीं (27 जनवरी 2011), 88वीं **(**15 मार्च 2011**)** और 89वीं (27 जून 2011) मंडल बैठकों में निविदा और मशीनरी के लिए अनुबंध प्रदान करने पर चर्चा हुई थी, किसी भी समय पर अर्द्ध-स्वचालित से पूर्ण स्वचालित कारखाने में विशेष वर्णन में परिवर्तन और परियोजना लागत में वृद्धि पर मंडल द्वारा प्रस्तुत या चर्चित नहीं हुआ था।

(ii) मंडल ने आदेश दिया (27 जून 2011) कि मशीनरी की लागत को सक्षम प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस मामले में, प्रशासक सक्षम प्राधिकारी (पूर्व प्रशासक ने जुलाई 2011 ने कार्यभार प्रदान किया था) था जिसे यूटीएल प्रशासन द्वारा प्रस्ताव रखा जाना चाहिए था। प्रशासक का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही प्रबंध निदेशक, एलडीसीएल. ने ₹6.84 करोड़ के लिए अनुबंध एक थाई फर्म को दे दिया था (जुलाई 2011)।

एलडीसीएल. अधिकारियों के साथ वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव की क्षमता में पूर्व प्रशासक द्वारा की गई बैठक में, मंडल की संपुष्टि किए जाने का निर्णय लिया गया था (अगस्त 2011)।

(iii) नई मशीनरी की आवश्यकता या उच्च लागत को प्रमाणित करने के एनआईएफपीएएटीटी के इनकार करने के बावजूद, निदेशक मंडल ने अपनी 91वीं बैठक (30 दिसम्बर 2011) में कार्योत्तर संपुष्टि स्वीकार की थी। स्पष्ट रूप से, मंडल के पास कही हुई बात को मान लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था क्योंकि इस समय तक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके थे (अगस्त 2011) और पूर्ण-स्वचालित मशीनरी के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया गया था।

4.1.3.4 नई मशीनरी की आवश्यकता और लागत की तर्कसंगतता को प्रमाणित करने से एनआईएफपीएचएटीटी का इनकार

उपरोक्त निर्णय का अनुसरण करते हुए, प्रबंध निदेशक, एलडीसीएल. ने निर्देश दिया (अगस्त 2011) कि उपकरण (₹3.24 करोड़ के एनआईएफपीएचएटीटी के मूल अनुमान के प्रति) के लिए ₹6.84 करोड़ की अधिक लागत की तर्कसंगतता को सुनिश्चित करने के लिए एनआईएफपीएचएटीटी से कहा जाए। विशेषज्ञ समिति के माध्यम से मामले की जांच करने के पश्चात् एनआईएफपीएचएटीटी ने इन आधारों पर अस्वीकृत किया (दिसम्बर 2011) (i) एनआईएफपीएचएटीटी के विशेषज्ञ सलाहकार ने उपलब्ध मछली पालन संसाधन और लक्षद्वीप के प्रक्षेपित संसाधन क्षमता के आधार पर अर्द्ध स्वचालित संयंत्र की अनुशंसा पहले की थी और (ii) पूर्ण स्वचालित मशीनरी की क्षमता और लागत को न्ययसंगत नहीं ठहराया गया था और पूर्ण-स्वचालित मशीनरी की लागत बहुत अधिक होनी थी पर पूर्ण स्वचालित मशीनरी की लागत की तर्कसंगतता का आकलन करने से इनकार कर दिया था।

4.1.4 बदले हुए कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अनुमानों को संशोधित करने में एलडीसीएल की विफलता

4.1.4.1 सिविल निर्माण कार्य अनुमानों को संशोधित करने में विफलता

एल डी सी एल. अर्द्ध-स्वचालित से पूर्ण-स्वचालित कारखाने से कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के परिणामस्वरूप सिविल निर्माण कार्यों और प्रशीतन में परिवर्तनों को शामिल करके एक नया डीपीआर तैयार करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा को अपने उत्तरों में, एलडीसीएल ने सूचित किया कि नई आवश्यकताओं को पूरा

करने के लिए डीपीआर को संशोधित करने के लिए नहीं कहा गया था। यह उत्तर अस्वीकार्य है। एलपीडब्ल्यूडी द्वारा अभिन्यास तैयार कर लिया गया था और वह मशीनरी की ऊँचाई और संरचना से परिचित थे। निर्माण को एलपीडब्ल्यूडी को सौंपा गया था और कारखाने की योजना कार्यकारी अभियंता द्वारा अनुमोदित की गई थी और सलाहकार, मछली पालन को एलडीसीएल द्वारा नियुक्त किया गया था। ग्राहक के रूप में, डीपीआर को संशोधित और अनुमोदित करना एलडीसीएल की जिम्मेदारी थी। एलडीसीएल ने न तो कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को समायोजित करने के लिए संशोधित अनुमान तैयार करने के लिए एलपीडब्ल्यूडी से निवेदन किया था और न ही कारखाने को योजनाओं को अनुमोदित करने के लिए कार्यकारी अभियंता या सलाहकार सक्षम है। संशोधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कारखाने की योजनाओं को संशोधित करने में एलडीसीएल की विफलता ही वह कारण है जिसकी वजह से आयातित मशीनरी को संस्थापित नहीं किया जा सका और खुले में महत्वपूर्ण उपकरण पड़ा हुआ होना जिससे उसे क्षति हो सकती थी जिसका उल्लेख पैरे में कहीं और भी किया गया है। एलडीसीएल द्वारा जमा किए गए (सितम्बर 2010) ₹3.51 करोड़ में से एलपीडब्ल्यूडी ने निर्माण कार्य का केवल कुछ भाग पूरा किया था (इस आधार पर कि संशोधित अनुमान अलाभकारी है) और दिसम्बर 2015 में एलडीसीएल को ब्याज (₹0.85 करोड़) सहित ₹1.62 करोड़ की राशि प्रदान की थी।

4.1.4.2 प्रशीतन अनुमानों को संशोधित करने में एलडीसीएल की विफलता

कैनिंग कारखाने के क्रियान्वयन के लिए न्यूनतम उत्पादन आवश्यकता को पूरा करने के लिए भंडारण और प्रशीतन आवश्यक है क्योंकि कैच बहुत कम है और मछली पकडने का मौसम वर्ष में छः माह तक सीमित है। तदनुसार, एनआईएफपीएचएटीटी ने ₹1.5 करोड़ पर अर्द्ध-स्वचालित कारखाने के लिए प्रशीतन प्रणाली का अनुमान लगाया था। हालांकि प्रशासक के कहने पर पूर्ण स्वचालित प्रक्रिया के लिए प्रशीतन प्रणाली हेतु अनुमान केवल ₹0.40 करोड़ के लिए अनुमोदित किया गया था जोकि अवास्तविक था और कारखाने को पूरी तरह से गैर-क्रियात्मक कर देता। यह प्रत्यक्ष हुआ जब, बाद में एलडीसीएल ने ₹32.15 करोड़ के लिए एक संशोधित डीपीआर का समर्थन किया (सितम्बर

2013) और उसे प्रस्तुत किया जिसमें एचवीएसी[8] और प्रशीतन लागत का अनुमान ₹6.53 करोड़ का लगाया गया था।

4.1.5 आयातित मशीन का संस्थापन न किया जाना

वैश्विक निविदा के पश्चात्, एलडीसीएल ने टूना कैनिंग कारखाने[9] के लिए मशीनरी की आपूर्ति, संस्थापन और कमीशन करने के लिए यूएसडी 1.49 मिलियन (₹6.84 करोड़) के लिए थायलैंड की फर्म (आपूर्तिकर्त्ता) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे (अगस्त 2011)। यद्यपि मशीनरी पहुंचा दी गई थी (मार्च 2012), यह इस आधार पर बिना खोले हुए पड़ी हुई है, कि एलपीडब्ल्यूडी ने सिविल निर्माण कार्य पूरे नहीं किए थे। चूंकि मशीनरी समुद्र के आस पास काफी लंबी अवधि के लिए बेकार पड़े रहने और मानसून के मौसम में बाहर होने के कारण मशीन पार्टो की कार्य करने वाली कार्य स्थिति संदेहपूर्ण है और वारंटी भी समाप्त हो चुकी होगी। एलपीडब्ल्यूडी ने प्रवेश द्वारा पर हॉरिजेंटल बीम काटने के लिए स्वीकृति दे दी थी जोकि नई इमारत में सबसे बड़ा डिब्बे का प्रवेश अवरूद्ध करता था परंतु आज तक इसे नहीं किया गया है (नवम्बर 2016) और मशीनरी अभी भी खुले में असंस्थापित पड़ी हुई है।

4.1.6 वित्त विभाग और मत्स्य पालन विभाग, संघ शासित क्षेत्र प्रशासन और कृषि और मत्स्य-पालन मंत्रालय एवं वाणिज्य मंत्रालय का वित्तीय नियमावली का अनुसरण करने में विफलता

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 26 और 52 से 56 इस प्रकार से निरूपित किए गए है जिसमें केन्द्रीय सरकार मंत्रालय और विभाग संसद द्वारा अनुमोदित बजट के प्रति व्यय को नियंत्रित करने की अपेक्षा की गई है और वर्ष के दौरान होने वाली बचतों को भी अभ्यर्पित करना होगा। केन्द्रीय सरकार प्राप्ति और भुगतान नियमावली का नियम 100 निर्धारित करता है कि वास्तविक रूप से किए गए सभी व्ययों का भुगतान और आहरण एक साथ किया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में उन्हे किसी अन्य वर्ष के अनुदान से भुगतान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; सरकारी खाते से

[8] हीटिंग वेंटीलेशन और एयर कंडीशनिंग

[9] कोयमबटूर की फर्म के साथ अलग अनुबंध के माध्यम से ₹0.40 करोड़ के लिए मछली अपशिष्ट का उपयोग करने वाले बायोगैस उत्पादन संयंत्र का प्रापण किया गया था।

तब धन का आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी आवश्यकता तत्काल संवितरण के लिए न हो। मांगों के पूर्वानुमान या बजट अनुदानों की चूक को रोकने के लिए सरकारी खाते से धन का आहरण करना स्वीकार्य नहीं है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि कृषि और मत्स्य-पालन मंत्रालय (राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹8.45 करोड़ और पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹2.00 करोड़) और वाणिज्य मंत्रालय (पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹3.24 करोड़) द्वारा पर्याप्त राशि जारी की गई थी (2009-10 और 2011-12 में), संबंधित वित्त वर्ष के दौरान उसे विस्तारित नहीं किया गया था। मंत्रालय ने जीएफआर में निर्धारित रूप से वित्त वर्ष के अंत तक बचतों का अभ्यर्पण सुनिश्चित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि वाणिज्य मंत्रालय ने कुल परियोजना लागत ₹7.64 करोड़ निर्दिष्ट की थी, प्रशासक (एलडीसीएल अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता में) ने वाणिज्य मंत्रालय को सूचित किए बिना अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करते हुए एकतरफा रूप से इसे ₹13.78 करोड़ (इसे वित्त विभाग, यूटीएल के माध्यम से किए बिना) तक संशोधित किया था जिसने वैसे भी संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय के रूप में अपनी क्षमता में पूर्व प्रशासक द्वारा की गई एक बैठक (अगस्त 2011) के अलावा परियोजना की प्रगति को मॉनीटर नहीं किया था। परियोजना पर ₹7.64 करोड़ की राशि का व्यय किया गया (दिसम्बर 2016) और एलडीसीएल के पास ₹6.89 करोड़ पड़े हुए थे।

वित्त विभाग, यूटीएल प्रशासन जिसने मत्स्य-पालन विभाग को निधियां जारी की थी, व्यय को मॉनीटर करने में विफल रहा। इसके अलावा, मत्स्य पालन विभाग को वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना उन परियोजनाओं से निधियों के पुर्नविनियोजन करने की अनुमति दी जा रही है जिन्हे बंद या स्थगित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, मत्स्य-पालन विभाग अतिरिक्त निधियों के लिए वित्त विभाग को मामला संप्रेषित किए बिना परियोजना लागत में ₹7.64 करोड़ से ₹13.78 करोड़ की वृद्धि के लिए एलडीसीएल की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को समायोजित कर पाया था। मत्स्य-पालन विभाग ने परियोजना की व्यवहार्यता और अतिरिक्त निधियों के एलडीसीएल से मांग की तर्कसंगतता की समीक्षा

नहीं की थी क्योंकि इन्हें अध्यक्ष, एलडीसीएल की क्षमता में प्रशासक द्वारा अनुमोदित किया गया था। मत्स्य-पालन विभाग ने लेखापरीक्षा को उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि मत्स्य-पालन विभाग की भूमिका वित्तीय सहायता तक सीमित थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह जीएफआर के नियम 26 विपरीत है जिसमें बताया गया है कि यह सत्यापित करना निधि संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का दायित्व है कि क्या निधियों का उचित रूप से उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हो रहा है जिसके लिए उसे संस्वीकृत किया गया था।

4.1.7 निर्यात दायित्वों को पूरा न करने के कारण सीमा शुल्क की देयता

एलडीसीएल ने इस शर्त पर कि वह छः वर्षों में ₹8.16 करोड़ की कीमत के टूना का निर्यात करेंगे मशीनरी के आयात पर ₹1.36 करोड़ के सीमा शुल्क की छूट[10] का लाभ उठाया है (अप्रैल 2012)। चूंकि, एलडीसीएल ने मशीनरी के आयात के पश्चात् टूना का निर्यात नहीं किया है, वह सीमा शुल्क प्राधिकारियों को लागू ब्याज के साथ संपूर्ण चुंगी की वापसी करने के लिए जिम्मेदार है। अपने उत्तर में, लेखापरीक्षा को एलडीसीएल ने सूचित किया (18 मई 2016) कि इस अवधि (अर्थात् अप्रैल 2018 तक) को बढ़ाया जा सकता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एलडीसीएल ने स्वीकार किया है कि उसने अपने आत्मविश्वास को सिद्ध करने के लिए कोई बाजार सर्वेक्षण संचालित नहीं किया था कि उसके निर्यातों के लिए अंर्तराष्ट्रीय बाजार और यदि महत्त्वपूर्ण मशीनरी चालू कर दी गई है तब भी कारखाना अंर्तराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता जोकि निर्यातों के लिए आवश्यक है।

4.1.8 निष्कर्ष

वित्त विभाग और मत्स्य-पालन विभाग यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि एलडीसीएल से निर्गत हुए प्रस्तावों को अपने निदेशक बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त था और प्रशासक के औपचारिक अनुमोदन के लिए वित्त और मत्स्य-पालन विभाग में विस्तृत संवीक्षा के पात्र नहीं थे। कृषि और मत्स्य-पालन विभाग एवं वाणिज्य मंत्रालय भी जीएफआर का अनुपालन सुनिश्चित करने में भी विफल रहे। परिणामस्वरूप, एलडीसीएल के पास ₹6.89 करोड़ का अवरोधन हुआ और

[10] निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना के अंतर्गत

टूना कैनिंग कारखाने के आधुनिकीकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति न होने के अलावा ₹7.64 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल रहा।

मामले को गृह मंत्रालय (जून 2015 और जनवरी 2017), कृषि और मत्स्य-पालन मंत्रालय (जनवरी 2017) एवं वाणिज्य मंत्रालय (जनवरी 2017) को भेजा गया था। उनके उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2017)।

नई दिल्ली
दिनांक: 02 मार्च 2017

(मुकेश प्रसाद सिंह)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 06 मार्च 2017

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक